भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2508
उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2022

ओडिशा में ब्रॉडबैंड कनेक्शन्स

2508. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में कार्यरत ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ब्यौरा और संख्या क्या है और चरण-। के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;
(ख) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ओडिशा में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टविटी प्रदान करने के लिए अवसंरचना प्राप्त जीपी का ब्यौरा क्या है;
(ग) सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या भारतनेट परियोजना के चरण-1 का खराब उपयोग हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु वाईफाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो ओडिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई प्रौद्योगिकी के फैलाव की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 10.01.2022 को प्रकाशित किए गए "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक" के अनुसार ओडिशा दूरसंचार सेवा क्षेत्र में कुल 2.09 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं।

भारतनेट परियोजना ओडिशा सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की जा रही है। ओडिशा में चरण-।। का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा राज्य आधारित मॉडल के माध्यम से किया गया है जिसके तहत 2946 योजनाबद्ध जीपी में से 2786 जीपी को सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा, 43 योजनाबद्ध ग्राम पंचायतों में से 22 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से सेवा उपलब्ध

जारी पृ.सं.2/-

कराने के लिए तैयार कर दिया गया है। चरण-I के तहत, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के माध्यम से कुल 3810 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें से 3809 ग्राम पंचायतों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार कर दिया गया है। दिनांक 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार ओडिशा में कुल 6617 ग्राम पंचायतों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार कर दिया गया है। हाल ही में भारतनेट के कार्यक्षेत्र को ओडिशा सहित देश की ग्राम पंचायतों से आगे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा ओडिशा सहित देश के सुदूरवर्ती गांवों में चरणबद्ध रूप से ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत ओडिशा के लिए निम्नलिखित स्कीमें तैयार की गई हैं:

(i) आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 7287 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम के तहत ओडिशा के सेवा से वंचित 3933 गांवों को शामिल किया गया है।

(ii) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों (चरण-II) में 2542 टावरों को संस्थापित करके 4जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम के तहत ओडिशा के लिए 483 टावर संस्थापित करना शामिल है।

(घ) से (च) भारतनेट परियोजना के तहत सृजित की गई अवसंरचना एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति है जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है और इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल आदि के माध्यम से ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

चरण-I के जीपी में ब्रॉडबैंड सुविधा (वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम कनेक्शन) उपलब्ध कराने का कार्य का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जा रहा है। दिनांक 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार भारतनेट चरण-I के तहत 2,511 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) जो भारतनेट परियोजना की निष्पादन एजेंसी है, ने भारतनेट चरण-I नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न राज्यों में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ 74 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौते में से चार अखिल भारत आधार पर (ओडिशा सहित) सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित हैं।

ओडिशा में भारतनेट चरण-II का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है जो इसके उपयोग के लिए भी उत्तरदायी है। हालांकि, चरण-II के अभी तक तहत कोई वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित नहीं किया गया है।

****